Now, Dr. Ashok Kumar Mittal - Demand to rename places having colonial names.

Demand to rename places having colonial names

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) **:** उपसभापति महोदय, आपने आज मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, भारत ने 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का शोषण सहा। राजनीतिक स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी हमारे हाई कोर्ट्स, रोड्स, अस्पताल, विश्वविद्यालय और कई ऐतिहासिक स्मारक ऐसे हैं, जो ब्रिटिश नामों को ढो रहे हैं, जो कि हमें गुलामी का एहसास दिलाते हैं। सरकार ने इस दिशा में कुछ ऐतिसाहिक कदम भी उठाए, जैसे 'राजपथ' को 'कर्त्तव्य पथ', 'इंडियन पीनल कोड' को 'भारतीय न्याय संहिता', 'इलाहाबाद' को 'प्रयागराज' करके एक राष्ट्रवादी सोच का परिचय दिया, लेकिन क्या यह इतना काफी है? आज भी हमारे कई हाई कोर्ट्स, जैसे बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ब्रिटिश इरा के नामों को ढो रहे हैं। कई institutions, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, भी British legacy के नाम के साथ चल रहे हैं। दिल्ली में ही कई रोड्स, जैसे कि मिंटो रोड, हेली रोड, चेम्सफोर्ड रोड, ये भी ब्रिटिश नामों को ही दर्शाते हैं।

सर, मुझे कुछ दिन पूर्व प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि शहर का नाम तो प्रयागराज हो गया, लेकिन वहां के हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। वहां का विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही ज्यादा माननीय विश्वविद्यालय है, उसका नाम आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। सर, और तो और वहां की जो लोक सभा constituency है, वह भी इलाहाबाद है, प्रयागराज नहीं। इसी तरह, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट के नामों पर भी हमें शायद विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड 3,600 से अधिक स्मारकों में आज भी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का घर है। दिल्ली में उस लेफ्टिनेंट एडवर्ड्स की कब्र है, जिसने 1857 की क्रांति में भारतीयों को बुरी तरह से कुचला था। ऐसे लोगों की समाधि को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनता का पैसा लगा रहे हैं। यहां तक कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की कब्र को भी उसी लेवल पर रखा गया है, जिस लेवल पर ताजमहल को रखा गया है। सर, यह थोड़ा-सा चुभता है।

सर, अब हम ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी हैं, इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इस तरफ विचार करें। कुछ राज्यों में भी ऐसा इश्यू है, जिसके लिए मैं वहां के मुख्य मंत्रियों को अलग से पत्र लिखकर निवेदन करूंगा। जैसे, वैस्ट बंगाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में मद्रास यूनिवर्सिटी तथा ऐसा ही कई और जगहों पर भी है, जहां के लिए मैं अलग से निवेदन करूंगा।

सर, यहां पर मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाए जो ब्रिटिश नामों वाले संस्थानों को....*

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

---

* Not recorded.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Dr. Ashok Kumar Mittal: Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Sujeet Kumar (Odisha). Now, Dr. Sikander Kumar - Demand to establish industrial units in the upper regions of Himachal Pradesh.

माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया हमेशा यह ध्यान में रखें कि जीरो ऑवर में आप जो भी मैटर उठाते हैं, वह स्ट्रक्चर्ड होता है और वह तीन मिनट से आगे जा ही नहीं सकता है, इसलिए उसको आप उतने समय में ही पूरा करें, धन्यवाद। डा. सिकंदर कुमार।

Demand to establish industrial units in the upper regions of Himachal Pradesh

डा .सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश) : मान्यवर, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार!

उपसभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के बद्दी, नालागढ़, जिला सिरमौर के काला अम्ब और जिला ऊना के गगरेट व संतोषगढ़ में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 350 बड़ी एवं मध्यम तथा लगभग 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महोदय, हिमाचल प्रदेश में अभी तक दो-तीन जिलों में ही औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और हिमाचल प्रदेश के बाकी जिले इससे वंचित हैं, जिससे वहां के लोगों के पास रोजगार के अवसर न के बराबर हैं और वहां के अधिकतर युवा या तो कृषि-बागबानी कर अपना गुजारा करते हैं या कोई छोटी-मोटी नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।

उपसभापति महोदय, सोलन, ऊना एवं सिरमौर की तरह ही हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी अगर छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं तो इससे वहां एक ओर उन क्षेत्रों का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर वहां के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे वहां के लोगों का जीवन और बेहतर हो सकेगा। महोदय, हिमाचल प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण वहां के अधिकांश युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में बाहरी राज्यों में जाने के लिए विवश हैं। ऐसे में यदि हिमाचल प्रदेश के मध्य एवं ऊपरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयां लगाई जाती हैं तो वहां के लोगों को उनके घर-द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ऐसा होने से हिमाचल प्रदेश भी दूसरे राज्यों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अपने राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Dr. Sikander Kumar: Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha). Now, Shri Ramji Lal Suman - Concern over foreign influence in Indian elections.